Government to fulfil its statutory obligation and constitute an appropriate Tribunal within a period of one month. The matter is being processed accordingly.

(c) No such proposal has been received at the Centre.

(d) and (e). Do not arise.

Income-tax exemption on donations for Jawahar Rojgar Yojna

1756. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government had received any proposal for granting exemption from income-tax the donations given for Jawahar Rojgar Yojna; and

(b) if so, what decision has been taken by Government thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Yes, Sir.

(b) Sections 35CCA and 80GGA of the Income-tax Act already provide for complete deduction in respect of donations to the Jawahar Rojgar Yojna, if routed through the National Fund for Rural Development.

मध्य प्रदेश में विकास-कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये पश्चिमी जर्मनी के साथ समझौता

1757. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 23 अक्तूबर, 1977 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा-आयाकट में विकास-कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये 4 करोड़ 50 लाख ड्यूश मार्क का ऋण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच समझौता हुआ था; यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1989 तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या समझौते में निर्धारित शर्तों के अनुसार तवा-आयाकट में सभी विकास कार्य पूरे हो चुके हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में चम्बल नियंत्रण क्षेत्र के विकास हेतु विश्व बैंक से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) जी हां, कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र में कमी के कारण ऋण की राशि बाद में घटाकर 193 लाख ड्यूश मार्क की गई थी। इस राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा चुका है।

(ख) इस परियोजना के भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 39015.786 हैक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। जिन क्रियाकलापों को अपनाया गया है वे हैं —जल निकास, सड़कें, गहन कृषि-विस्तार अनुकूल अनुसंधान परीक्षण, सर्वेक्षण, योजना, खेत पर विकास, भूमि की चकबन्दी, फसल मुआवजा, बाड़ाबंदी आदि।

(ग) इस प्रयोजन के लिए 550 लाख अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता का उपयोग कर लिया गया है।

मैसर्स गोल्डन इन्टरप्राइजेज, दानापुर (बिहार) के बीमा संबंधी दावे

1758. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोल्डन इन्टरप्राइजेज दानापुर, बिहार ने स्टेट बैंक, दानापुर के माध्यम से नैशनल इंश्योरेंस कंपनी पटना के साथ अपना बीमा कराया था, जिसमें बाढ़ का खतरा भी शामिल था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1975 की ऐतिहासिक बाढ़ के कारण गोल्डन इन्टरप्राइजेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उक्त कारखाना उसी समय से बंद है तथा बीमा कंपनी द्वारा उसे अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार इस संबंध में कब तक दावों का निपटारा करने तथा कंपनी को भुगतान करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री): (क) मैसर्स गोल्डन इन्टरप्राइजिज, दानापुर (बिहार) ने आग, दंगों तथा हड़ताल के जोखिमों के लिए, न कि बाढ़ के जोखिम के लिए भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, से बीमा पालिसी प्राप्त की थी।

(ख) और (ग). चूंकि इस मामले में "बाढ़